बैंकों में घटता जन-विश्वास चौकीदार की चौकीदारी ले कर रहेगा....

ग्राउंड जीरो से विवेक की रिपोर्ट

डिजिटल इंडिया में कैसे आपकी जेब काटी जाए इसकी पूरी तैयारी के साथ भारत सरकार ने आमजन के सामान्य एटीएम् कार्ड बंद कर दिए हैं और उसके स्थान पर आये हैं नए कांटेक्टलेस एटीएम् कार्ड। एक जनवरी से ग्राहकों को जारी हो रहे अधिकांश कार्ड ऐसे ही हैं जिनमे बिना पिन डाले और बिना स्वाइप किये रकम भेजी जा सकती है और तेज खरीदारी की जा सकती है।

भाजपा के बागी संसद शत्रुघ्न सिन्हा मोदी सरकार को वन मैन शो और टू मैन आर्मी कहते हैं। उनके हिसाब से दोनों फेल। डिजिटल इंडिया बना कर अच्छे दिनों के वादे के साथ आये मोदी राज में बुरे दिन इस कदर घुस गए हैं जिनसे पार पाना मुश्किल जान पड़ता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तराजू पर तौलें तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि देश को जुमलों का भरता बनाने के बाद उसे लीलने की कसर भर बाकी है। स्वर्प्रथम आर्थिक रूप से भारत की सशक्तता को मापें तो बुनियाद हिलती दिख रही है और नौकरशाही के लूट तंत्र को बनाये रखने में कोई कसर सरकार ने उठा नहीं रखी है।

सरकार का दावा है कि एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में होने वाले कुल वित्तीय लेन-देन में 60 प्रतिशत दो हजार से कम में होता है। इसे आसान बनाने के लिए ही कांटेक्टलेस कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। भारत में पहली बार वीजा ने 2015 में ऐसे कार्ड जारी किये थे तबसे अब तक 2 करोड़ कार्ड जारी किये जा चुके हैं। वीजा के मुताबिक भारत में ऐसे कार्ड सपोर्ट करने वाले 10 लाख से ज्यादा टर्मिनल हैं।

अब बात करते है इस कार्ड की उस तथाकथित खासियत की जिसके लिए ग्राहक को बिना पूर्ण जानकारी दिए सरकार ने इसे सभी पर लाद दिया है। कार्ड की खासियत यह है कि एक बार में दो हजार तक की रकम इस कार्ड से बिना पिन या ओटीपी के काटी जा सकटी है। एचडीएफसी बैंक मुनिरका दिल्ली के शाखा प्रबंधक कमल के अनुसार ये कार्ड पहले वाले कार्डों से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि पहले पेमेंट करने के लिए ग्राहक को कार्ड दुकानदार के हाथ में देना पड़ता था जिसे वह स्वाइप करता था और इस तरह कार्ड की क्लोनिंग का खतरा बढ़ जाता था। अब क्योंकि यह कार्ड ग्राहक के हाथ में रहेगा इसलिए क्लोनिंग हो ही नहीं सकती कार्ड की। और तो और सुरक्षा के साथ-साथ पेमेंट भी तेज हो सकेगा।

पेमेंट कैसे तेज होगा? इस पर मैनेजर साहब का जवाब चौंकाने वाला था। प्रबंधक ने बताया कि अब दो हजार तक के भुगतान के लिए कार्ड को मशीन में नहीं डालना होगा क्योंकि कार्ड को इस तरह बनाया गया है कि मशीन के 4 सेन्टीमीटर करीब लाते ही पेमेंट ऑटोमेटिक रूप से हो जाएगा। मतलब कि न कोई पिन न ओटीपी।

जिस फीचर को बैंक सुरक्षा का मानक बता रहा है वो क्या सच में सुरक्षा मानक है? कार्ड हाथ में रहने से क्लोनिंग नहीं हो सकती पर मशीन तो किसी के हाथ में भी हो सकती है। सोचा जा सकता है कि हम भीड़ भरी मेट्रो में सफर कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति मशीन में दो हजार की रकम भर कर हमारी जेबें खाली करता जाए। बड़ी बात ये कि जेब खाली होती जाएगी और भीड़ भरी मेट्रो में फोन निकाल कर एसएमएस पढ़ पाने की स्थिति में आप होंगे ही नहीं।

ऐसे ही एक कार्ड का इस्तेमाल कर रहे चौधरी प्रधान सिवाल ने बताया कि अपने परिवार के साथ वह फिल्म देखने गए। टिकट के पैसे देने के लिए उन्होंने अपना नया जारी एटीएम् कार्ड दिया और जब बिना पिन मांगे ही काउंटर वाले ने बताया कि पेमेंट हो गई तो चौधरी अवाक रह गये। ऐसा कैसे हुआ तो इसपर एग्जीक्यूटिव ने बताया कि आपका कार्ड कांटेक्टलेस है।

नए कार्ड की सुरक्षा से जुड़े सवालों के लिए हमने एचडीएफसी बैंक के कस्टमर केयर में फोन किया और पुछा कि मेरा कार्ड खो गया है यदि किसी और को मिल गया तो क्या होगा? ग्राहक सेवा केंद्र प्रतिनिधि ने बताया कि इस स्थिति में हमें तुरंत बैंक को सूचित कर कार्ड ब्लाक करना पड़ेगा। यदि मेरी जानकारी में आने से पहले ही किसी ने शॉपिंग कर ली तो नुकसान की भरपाई बैंक करेगा।

कुछ बैंकों के मुताबिक अगर एक दिन की कार्ड लिमिट 25 हजार रुपये है तो इतने पैसों का नुकसान हो सकता है। लेकिन इस कार्ड से उसके लिए 12 बार पेमेंट लेना होगा। आईसीआईसीआई बैंक के साथ अन्य कई बैंकों के ग्राहक सेवा केंद्र में बात होने पर बताया कि ग्राहक को स्वयं अपने कार्ड की सुरक्षा करनी होगी, एवं उसे संभाल कर रखना होगा। कार्ड चोरी होने या गिरने पर ग्राहक को कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि ग्राहक ने यह साबित कर दिया कि उसकी गलती से नहीं बल्कि किसी और कारण से पैसा निकल गया है तभी बैंक मुआवजा देगा। मुआवजा क्या होगा इसकी कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी।

बैंक आफ इंडिया पंचशील ब्रांच की मुख्य शाखा प्रबंधक उफमा निदा सिद्दीकी ने कहा कि उनका बैंक फिलहाल चिप आधारित कार्ड ही इस्तेमाल कर रहा है और यह पहले जारी किये गए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड से ज्यादा सुरक्षित है। पर जिस कांटेक्टलेस कार्ड का जिक्र हम कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी अभी उन्हें नहीं है। पर वो यह मानने को तैयार नहीं कि इतनी खतरनाक अवस्था वाला कार्ड सरकार लाएगी। जरूर कुछ ऐसा है जो अभी हमे नहीं मालूम इसलिए हमे आशावादी रहना चाहिए जब तक की पूरी जानकारी इस कार्ड के सन्दर्भ में न मिल जाए। यानी बैंक स्वयं अँधेरे में हैं।

बीते 8-9 जनवरी को केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल में बैंक कर्मियों ने भी योगदान दिया और दो दिन बैंकों में भी काम ठप ही रहा लगभग। कारण था बैंक आफ बड़ोदा और अन्य दो बैंकों का विलय। बैंक कर्मियों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण बैंक डूब रहे हैं और सिर्फ अपना चुनाव जीतने के लिहाज से बनायीं जाने वाली सरकारी नीतियाँ देश हित में नहीं है।

उर्जित पटेल ने सरकार से खफा होकर इस्तीफा दे दिया और अब तक अपने कपडे-लत्ते बाँध कर विदेश जाने की तैयारी कर चुके होंगे। डूबते जहाज से भागने वाले चूहों में एक और नाम शामिल होने वाला है, ऐसी उम्मीद है।

सरकार की आर्थिक नीतियाँ कितनी कमजोर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकार ने जिस वार्षिक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के लिए 3.5 प्रतिशत की सीमा तय की हुई थी वो वो सीमा नवम्बर माह में ही पूरी हो गई। चुनावी मौसम में ये नुकसान अभी और बढ़ने की उम्मीद है।

बैंकों की हालत बहुत खराब है और सरकार की तरफ से मौखित आदेश टॉप मैनेजमेंट को दिया गया है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा नकदी अपने पास ही रखे। नोटबंदी जैसा बेवकूफाना कदम देश की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खाता ही जाएगा।

आरबीआई ने सरकार को चेताया है कि मुद्रा लोन में अब तक 11000 करोड़ रूपया एनपीए हो चुका है जिसके भविष्य में बढ़ने की आशंका है। बैंकों ने मोदी को चेताया है कि पहले से ही एनपीए की समस्या दानव बनी बैठी है जिसमे मोदी के यारों का एनपीए इतना है कि बैंक चरमराने तक की कगार पर जा रहे हैं। अब सरकार की नजर आरबीआई के कोष पर है। जिसका लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा लेकर सरकार बैंकों के माध्यम से अपने यारों में बांटने को आतुर है। एनपीए से सरकार को कोई मतलब नहीं। बस चुनाव जितना ही मकसद है।

क्योंकि चुनाव पास हैं तो सरकार आंकड़ों के खेल में उलझा कर सिर्फ एक ऐसा नंबर दिखाना चाहती है जिससे लगे कि सरकार ने बड़ा फायदा कमाया है। इसके लिए सरकार ने विनिवेश को ही चुना है। अपनी पेंशन जारी रख बाकी सबकी बंद कर देने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक विनिवेश मंत्रालय बना डाला था। तबसे लेकर आजतक सरकारें अपनी परिसंपत्तियां बेच कर अम्बानी-अदानी से पक्की दोस्ती निभा रही हैं। बेचने में माहिर भाजपा ने प्रतिवर्ष लगभग एक लाख करोड़ की परिसम्पतियाँ बेचीं हैं और कोशिश की है कि जनता यही मानती रही कि देश को ये पैसा फायदा स्वरूप मिला है।

अब नए विनिवेश के तहत सरकार ने सभी बैंकों को अपनी हिस्सेदारी बेच कर 52 प्रतिशत तक लाने के आदेश दिए हैं। यदि सभी 21 सरकारी बैंक अपने शेयर बेच कर हिस्सेदारी 52 प्रतिशत तक सीमित करें तो 65612 करोड़ की रकम बैंक के पास आएगी। जाहिर है सरकार अपने वोटरों को दिखाना चाहेगी कि पहली तिमाही में ही कितना मुनाफा मोदी ने निकाला दिया। उधार लेकर घी खाने की परम्परा से आगे बढ़ते हुए ये बर्तन बेच कर घी खाने जैसा ही है।

अब जब अर्थव्यवस्था मृत्युशय्या पर पड़ी है तो मोदी जी ने अपना आखरी तीर भी चला दिया। बैंक कर्मियों को अपने ही बैंक का बांड खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। अधिकारी को 2.5 लाख और क्लर्क को 1.5 लाख तक का अपने बैंक के जारी बांड खरीदने का दबाव है। ये बांड खरीदने के लिए कोई लोन नहीं दिया जाएगा बल्कि कर्मचारियों को निर्देश हैं कि अपनी बचत से ये रूपया खर्च करें।

इन गलाघोटू नीतियों ने एक तरफ जहाँ कर्मचारियों में रोष पैदा किया है वहीँ बैंकों की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हुई है। अपने कुरते की क्रीज न बिगड़ने देने वाले मोदी ने अर्थव्यवस्था को मोड़तोड़ कर एक मटके में डाला हुआ है। और ये सब सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। विनिवेश और जबरन ब्रांड बेच-बेच कर सरकारी कंपनियों को गर्त में पहुंचाने वाली सरकार के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके यार अम्बानी ने रिकॉर्ड बनाते हुए पहली तिमाही में हे 10 हजार करोड़ का मुनाफा कमा लिया है।

सवाल ये है कि जब चिप आधारित कार्ड से काम चल रहा है तो फिर ये कांटेक्टलेस असुरक्षित कार्ड क्यों? फिलहाल हम बैंक मेनेजर उफमा की बात मान आशावादी बने रह सकते हैं।

नोटबंदी से जगजाहिर हो चुका है कि आर्थिक फ्रंट पर सरकार कितनी अपरिपक्वता के साथ काम कर रही है। मोटा-मोटी सरकार चाहती है कि बैंकों का पैसा बैंकों में रहे, न कि ग्राहक कैश का इस्तेमाल करे। ग्रामीण हल्कों में तो बैंक लोगों को उन्ही का पैसा कैश में देने में आनाकानी कर रहे हैं।

गोरखपुर बांसगांव तहसील उत्तरप्रदेश में 69 वर्षीय श्रीराम राय को अपने 50 हजार रुपये निकालने के लिए एसबीआई बैंक ने ये कह कर टाल दिया कि इतनी बड़ी रकम ग्रामीण अंचल में हम आपको कैश में नहीं दे सकते। झगडा बढ़ने की सूरत में मैनेजर ने माफी मांगते हुए कहा कि क्या करें साहब सरकार का दबाव है कि कम से कम कैश बाहर जाए।

फरीदाबाद के जगदीप सिंह संधू सेक्टर 28 के पीएनबी ब्रांच से अपना पैसा निकालने आये थे। 65 वर्षीय संधू ने कहा कि बैंकों में लोगों का विश्वास नोटबंदी के बाद से कम होता चला जा रहा है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं बैंक किसी न किसी बहाने खाताधारकों के पैसे काट रहा है। अब आप देखो जब पासबुक अपडेट कराते हैं तभी कुछ न कुछ नया खर्च जुड़ा मिलता है। ऊपर से अब ये नए एटीएम् कार्ड लेने का झंझट।

रोज जनता की जेब से पैसे निकाल कर पूंजीपतियों की जेबें भरने वाली मोदी सरकार के नए नियमों से आम आदमी इतना परेशान और असुरक्षित महसूस करने लगा है कि उसका बैंक में भरोसा कम हो गया है। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि सरकार को नोटबंदी के बाद से बैंक में पैसा रुका रहे और लोग कैश न निकाल लें, सारा उसके लिए रोज नए-नए नियम बनाने पढ़ रहे हैं।

मोदी ने 2014 के चुनाव में दावा किया था कि वो गुजरात से हैं और व्यापार उनके खून में है। पर मोदी को शायद ये नहीं मालूम कि व्यापार में विश्वास का बने रहना बहुत जरूरी पक्ष है। सूरत का हीरा व्यापारी करोडों के हीरे एक मुलाजिम को हाथ में देकर दूसरे व्यापारी से कैश लाने भेजता है सिर्फ विश्वास पर। इसी प्रकार बैंक में जनता का भरोसा बना रहेगा तो आपको रोज नए नियम लागू करने की जरूरत नहीं होगी। 'ईज आफ डूइंग बिजनेस' में सुरक्षा और विश्वास सबसे प्रमुख कारक होते हैं जबकि डर और अविश्वास के माहौल में व्यापार आसानी से हो ही नहीं सकता।

बोर्ड पर लिखी रकम देखिए जो कुंभ मेले पर खर्च की जानी है, और बोर्ड के नीचे बैठे परिवार की दशा को देखिए। धर्म की आड़ में विषमता!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06